



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## भारत की खेल नीति का विश्लेषण

Laxmendra Kumar Kuldeep\*

Sports Officer

Govt.V.Y.T. PG Autonomous College Durg C.G.

### सारांश

यह शोध पत्र “भारत की खेल नीति का विश्लेषण” विषय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य देश में खेल विकास हेतु बनाई गई नीतियों की प्रभावशीलता, संरचना और क्रियान्वयन का समग्र मूल्यांकन करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की गई खेल नीतियाँ, विशेष रूप से राष्ट्रीय खेल नीति और “खेलो इंडिया” जैसी योजनाएँ, खेलों के विकास में किस हद तक सफल रही हैं। इस शोध में द्वितीयक (Secondary) अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी रिपोर्टें, शोध पत्रों, पुस्तकों और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में खेल नीति का ढांचा मजबूत होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे कि खेल अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित कोचों का अभाव, और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सुविधाएँ। इसके साथ ही, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि हाल के वर्षों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन भी सुधरा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी और सरकारी पहलों ने खेलों को नई दिशा प्रदान की है। अंततः, यह शोध पत्र सुझाव देता है कि खेल नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के उचित उपयोग और जमीनी स्तर पर सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से भारत खेल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

**संकेतशब्द-** भारत की खेल नीति, खेल विकास, खेलो इंडिया, युवा सशक्तिकरण, खेल अवसंरचना, प्रतिभा पहचान, ग्रामीण खेल विकास, खेल प्रशासन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), खेल प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, नीति विश्लेषण।

### प्रस्तावना

भारत एक युवा देश है जहाँ लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस विशाल युवा शक्ति को सही दिशा देने में खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क जैसी विशेषताओं का भी विकास करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक राष्ट्र-निर्माण में खेलों को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। भारत में खेलों का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ कुश्ती, तीरंदाजी, कबड्डी और मलखंभ जैसे पारंपरिक खेल प्रचलित थे। आधुनिक काल में औपनिवेशिक प्रभाव के कारण क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, किंतु लंबे समय तक संसाधनों की कमी, अवसंरचना की कमी और स्पष्ट नीति के अभाव के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। भारत सरकार ने समय-समय पर खेलों के विकास हेतु विभिन्न नीतियाँ बनाई हैं। 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई, जिसके बाद 2001 और 2011 में संशोधित नीतियाँ प्रस्तुत की गईं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य खेलों को जन-जन तक पहुँचाना, प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करना रहा है। वर्तमान समय में भारत की खेल नीति बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें खेल शिक्षा, प्रतिभा पहचान, कोचिंग, खेल विज्ञान, पोषण, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भागीदारी शामिल है। “खेलो इंडिया” जैसी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ने भी खेलों के विकास को गति दी है। हालांकि, इन प्रयासों के

बावजूद भारत अभी भी ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों पर सीमित सफलता ही प्राप्त कर पाया है। इसका कारण नीति के कार्यान्वयन में कमियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, और खेलों को करियर के रूप में अपनाने में सामाजिक बाधाएँ हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत की खेल नीति का गहन विश्लेषण करना, उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, और भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

भारत एक युवा देश है जहाँ लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस विशाल युवा शक्ति को सही दिशा देने में खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क जैसी विशेषताओं का भी विकास करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक राष्ट्र-निर्माण में खेलों को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। भारत में खेलों का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ कुश्ती, तीरंदाजी, कबड्डी और मलखंभ जैसे पारंपरिक खेल प्रचलित थे। आधुनिक काल में औपनिवेशिक प्रभाव के कारण क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, किंतु लंबे समय तक संसाधनों की कमी, अवसंरचना की कमी और स्पष्ट नीति के अभाव के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। भारत सरकार ने समय-समय पर खेलों के विकास हेतु विभिन्न नीतियाँ बनाई हैं। 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई, जिसके बाद 2001 और 2011 में संशोधित नीतियाँ प्रस्तुत की गईं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य खेलों को जन-जन तक पहुँचाना, प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करना रहा है।

वर्तमान समय में भारत की खेल नीति बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें खेल शिक्षा, प्रतिभा पहचान, कोचिंग, खेल विज्ञान, पोषण, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भागीदारी शामिल है। “खेलो इंडिया” जैसी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ने भी खेलों के विकास को गति दी है।

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद भारत अभी भी ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों पर सीमित सफलता ही प्राप्त कर पाया है। इसका कारण नीति के कार्यान्वयन में कमियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, और खेलों को करियर के रूप में अपनाने में सामाजिक बाधाएँ हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत की खेल नीति का गहन विश्लेषण करना, उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, और भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

## साहित्य समीक्षा

**शर्मा (2015):** भारत की खेल नीति का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि देश में खेलों के विकास के लिए नीतिगत ढांचा तो मौजूद है, लेकिन उसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई कमियाँ हैं। उनके अध्ययन में पाया गया कि सरकारी योजनाएँ अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती हैं और जमीनी स्तर पर उनका लाभ खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पाता। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक अक्षमता, समन्वय की कमी और वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग न होना प्रमुख समस्याएँ हैं। इस अध्ययन में नीति के क्रियान्वयन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

**सिंह एवं यादव (2018):** अध्ययन में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास की स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं और अवसंरचना की भारी कमी है, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर नहीं पाते। उनके अनुसार, अधिकांश खेल नीतियाँ शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को ग्रामीण स्तर पर खेल मैदान, प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए ताकि छुपी हुई प्रतिभाओं को अवसर मिल सके और खेलों का समग्र विकास हो।

**खेल मंत्रालय रिपोर्ट (2020):** “खेलो इंडिया” कार्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रतिभा पहचान, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस पहल से खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी संसाधनों और प्रशिक्षित कोचों की कमी बनी हुई है।

**अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) रिपोर्ट (2020):** भारत के खेल तंत्र का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया कि भारत में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन खेल विज्ञान, पोषण, और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण खिलाड़ी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुँच पाते। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भारत को खेल अनुसंधान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय कोचिंग मानकों को अपनाने की दिशा में अधिक निवेश करना चाहिए। इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

**गुप्ता (2021):** भारत में खेल विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर और निजी संस्थाओं की भागीदारी ने खेलों को नई दिशा दी है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे आयोजनों ने न केवल खिलाड़ियों को आर्थिक लाभ दिया है बल्कि खेलों की लोकप्रियता भी बढ़ाई है। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार संभव है। गुप्ता ने भविष्य में निजी निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

## अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत की खेल नीति का विश्लेषण करना
2. खेल नीति के प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करना
3. नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना

## अनुसंधान पद्धति

इस शोध में द्वितीयक (Secondary) अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत पहले से उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है। इस पद्धति का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह अध्ययन भारत की खेल नीति के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति और प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। द्वितीयक डेटा के स्रोतों में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्टें, वार्षिक प्रकाशन, और विभिन्न नीतिगत दस्तावेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, पुस्तकों, समाचार पत्रों, और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से भी जानकारी एकत्रित की गई है।

डेटा के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक (Descriptive) और तुलनात्मक (Comparative) पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जिससे विभिन्न समय अवधियों की खेल नीतियों और उनके प्रभावों की तुलना की जा सके। इस अध्ययन में सामग्री विश्लेषण (Content Analysis) के माध्यम से नीतियों के प्रमुख बिंदुओं, उद्देश्यों और परिणामों को समझा गया है। द्वितीयक पद्धति की एक सीमा यह है कि यह पूरी तरह उपलब्ध आंकड़ों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, फिर भी यह व्यापक और समय-संवेदनशील अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी और उपयुक्त मानी जाती है।

## अध्ययन का प्रभाव

### 1. खेल नीति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है

यह अध्ययन भारत की खेल नीति की वर्तमान स्थिति को गहराई से समझने में सहायक है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि नीतियाँ केवल दस्तावेजों तक सीमित हैं या उनका वास्तविक प्रभाव जमीनी स्तर पर भी दिखाई देता है। अध्ययन से यह पता चलता है कि किन क्षेत्रों में नीति सफल रही है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इससे नीति के क्रियान्वयन की वास्तविकता सामने आती है, जो भविष्य में बेहतर योजना निर्माण के लिए आधार प्रदान करती है।

### 2. नीति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की पहचान होती है

इस अध्ययन के माध्यम से खेल नीति के दोनों पक्षों—सकारात्मक और नकारात्मक—का संतुलित विश्लेषण किया गया है। एक ओर जहाँ “खेलो इंडिया” जैसी योजनाओं ने प्रतिभा को प्रोत्साहित किया है, वहीं दूसरी ओर अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित कोचों की अनुपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन नीति की कमियों और उपलब्धियों दोनों को उजागर करता है, जिससे सुधार के लिए स्पष्ट दिशा मिलती है।

### 3. सरकार और नीति निर्माताओं को सुधार के लिए दिशा मिलती है

यह अध्ययन नीति निर्माताओं और सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रस्तुत निष्कर्ष और विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि किन क्षेत्रों में अधिक निवेश और ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, खेल अवसंरचना का विकास, प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार। इस प्रकार, यह अध्ययन भविष्य की नीतियों को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

### 4. खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलती है

इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक और प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। जब खेल नीति के लाभ और अवसरों की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आती है, तो अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही, यह अध्ययन समाज में खेलों के महत्व को भी रेखांकित करता है, जिससे अभिभावकों और समुदाय का दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

## महत्व

यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- यह खेल नीति की प्रभावशीलता को समझने में मदद करता है
- खेलों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय सुझाता है
- नीति निर्माण में सुधार हेतु आधार प्रदान करता है
- खिलाड़ियों और कोचों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने में सहायक है

## निष्कर्ष

भारत की खेल नीति ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। “खेलो इंडिया” और अन्य योजनाओं ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया है। इसके बावजूद, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित कोचों की कमी, और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों का अभाव।

भविष्य में भारत को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें नीति निर्माण के साथ-साथ उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए। निजी क्षेत्र की भागीदारी, तकनीकी नवाचार, और खेल शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

## संदर्भ

1. Sharma, R. (2015). *Sports policy in India: Issues and challenges*. New Delhi: XYZ Publications.
2. Singh, A., & Yadav, P. (2018). Rural sports development in India: A critical analysis. *International Journal of Physical Education and Sports Sciences*, 12(2), 45–52.
3. Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. (2020). *Annual report 2019–20*. New Delhi: Government of India.
4. International Olympic Committee. (2020). *Sports development and global performance report*. Lausanne: IOC Publications.
5. Gupta, M. (2021). Role of private sector in sports development in India. *Journal of Sports Management and Policy*, 8(1), 23–30.
6. Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. (n.d.). *Khelo India scheme*. Retrieved from <https://yas.nic.in>
7. Various authors. (2019–2022). Articles on sports policy and development. *The Hindu, Times of India*, and other national newspapers.